(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत और अधिक सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) गुजरात के कच्छ जिले में केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने का वर्ष	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हजार हेक्टेयर)
1.	मित्ती	1985.86	2.36
2.	मतल	1985.86	2.21
3.	नारा	1990.91	2.31
4.	सुवी	1990.91	3.19
5.	निरूणा	1990.91	3.04
6.	कौला	1990.91	3.24

(ख) से (ग) केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास में शामिल करने के लिये गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	कृषि योग्य कमान क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	पिगुता सिंचाई योजना	481.84	1406
2.	बलदेवा	540.12	2240
3.	चोपादादाव	908.23	1460
4.	काकेडियाम्बा	812.88	891
5.	लखीगम	395.00	800

(घ) और (ङ) पिगट सिंचाई योजना और बलदेवा सिंचाई योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा इन्हें केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया है।

Irrigation Potential at the end of Seventh Plan

3425. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the state-wise irrigation potential created at the end of the Seventh Five Year Plan in the M & M Sector and subsequent year together with Government's investment on creating irrigaiton potentiality so far;

(b) whether it is a fact that Government have revised the irrigation potential created by the end of Seventh Plan from 34.8 mh to 29.9 mh as has been commented in the Economic Times of July 27-28, 1994 and the Annual Report of 1992-93, if so, what are the reasons and what are the facts in this regard; and

(c) what is the quantum of unutilised irrigation potential at the end of Seventh Plan and in the subsequent year. State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) and (c) A statement showing State-wise irrigation potential created an unutilised irrigation potential at the end of Seventh Plan and 1991-92 through Major & medium irrigation projects and plan expenditure during 1951—92 is given in the enclosed Statement.

(b) At the instance of Planning Commission, Irrigation Potential Created through Major & medium projects was reappraised at the end of Sixth Plan to correct the over-reporting and other inacccuracies on the basis of data furnished by State Governments. The potential created at the end of Sixth Plan was firmed up at 27.70 million hectares in place of the earlier figure of 30.01 million hectares. Accordingly, the figure of irrigation potential created at the end of Seventh Plan was revised at 29.92 million hectares and the same has been reflected in the Annual Report 1992-93.

Statement

(Rs. Crores/rhuusand Hectares)

s. No	State/UTs S	Irrigation Potential Created at the end of		Unutilised at the end of		Total Plan Expenditure 1951-92
		eventh Plan (1985-90)	Annual Plan (1991-92)	Seventh Plan (1985-90)	Annual Plan (1991-92)	
1.	Andhra Pradesh	2991	2999	155	152	3445.10
2.	Arunachal Pradesh	—	—	—	—	2.38
3.	Assam	144	176	47	65	287.55
4.	Bihar	2743	2766	484	471	3132.60
5.	Goa	13	13	8	1	111.77
6.	Gujarat	1199	1246	344	260	3472.07
7.	Haryana	2021	2035	230	244	1184.17
8.	Himachal Pradesh	8	8	2	4	26.54
9.	Jammu & Kashmir	158	158	41	22	206.11
10.	Karnataka	1308	1377	125	185	1875.70
11.	Kerala	402	416	47	49	908.22
12.	Madhya Pradesh	1815	1962	546	567	2885.56
13.	Maharashtra	1986	2030	1010	994	4419.41
14.	Manipur	59	59	13	9	196.71
15.	Meghalaya	—	—	—	—	1.37
16.	Mizoram	—	—	—	—	0.50
17.	Nagaland	—	—	—	—	0.25
18.	Orissa	1356	1409	102	83	1530.20
19.	Punjab	2344	2367	41	58	722.53
20.	Rajasthan	1913	1999	173	112	1667.41
21.	Sikkim		—	—	—	1.10
22.	Tamil Nadu	1539	1545	3	4	643.04
23.	Tripura	2	2	0	—	65.24
24.	Uttar Pradesh	6667	6806	962	1043	3666.17
25.	West Bengal	1244	1353	112	95	67.93
	Total (States)	29912	50726	4445	4418	30519.63
	Total (UTs)	8	15	8	8	117.29
	Total (All India)	29920	30741	4453	4426	30636.92

मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना

3426. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में बिलासपुर के पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कल्याण मंत्रालय ने योजना को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो वित्तीय मंजूरी कब तक दे दी जाएगी और राज्य सरकार को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के बिलासपुर प्रभाग की समेकित आदिवासी विकास परियोजना के लिए परियोजना रूपरेखा तैयार की है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम द्वारा वित्त पोषित किया जाना है। परियोजना 45 आदिवासी विकास प्रखंडों के लिए अभीष्ट है जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 59% है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) यह परियोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रीय